



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 7, 2019/ कार्तिक 16, 1941

No. 352]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 7, 2019// KARTIKA 16, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

(द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2019

[प्रकरण सं. (एस जी) 07/2019]

विषय : भारत-कोरिया विस्तृत आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच) नियमावली, 2017 के तहत कोरिया से भारत में “पोलिबूटाडिन रबड” के आयातों के संबंध में द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरुआत की सूचना।

फा. सं. 22/7/2019.—डीजीटीआर: एक आवेदन मैसर्स रिलाइंस इंडस्ट्रीज लिमि. (इसके पश्चात ‘आवेदक भी कहा गया है) द्वारा भारत-कोरिया विस्तृत आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच) नियमावली, 2017 (जिसे इसके पश्चात “उक्त नियमावली” भी कहा गया है) ने कोरिया आरपी (जिसे इसके पश्चात “संबद्ध देश” भी कहा गया है) से “पोलिबूटाडिन रबड” (जिसे इसके पश्चात “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” अथवा “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के बड़े हुए आयातों जिसके कारण भारत में इसी प्रकार के घरेलू उत्पादक अथवा सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पाद से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है, का आरोप लगाते हुए दायर किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

- विचाराधीन उत्पाद “पोलिबूटाडिन रबड” है जिसे एचएस कोड 40 02 20 00 के तहत वर्गीकृत किया गया है। पोलिबूटाडिन रबड (जिसे पीबीआर भी कहा गया है) एक सिंथेटिक रबड है जो मोनोमर 1, 3-बूटाडिन के पोलिमेराइजेशन से बना एक पोलिमर है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से टायरों के विनिर्माण में किया जाता है और पोलिस्ट्रिन और एकरिलोनिट्रिल बूटाडिन स्ट्रइन के रूप में भी किया जाता है। उत्पाद एक से अधिक ग्रेड में उत्पादित

किया जाता है। आवेदक ने उत्पादन में प्रयोग किए गए कैटालिस्ट के आधार पर अन्तर करते हुए 5 ग्रेडों में अभिचिन्हित किया है। आवेदक के अनुसार ग्रेड नियोडिमियम, कोबाल्ट, निकैल, टिटैनियम और लिथियम के रूप में अभिचिन्हित किया जा सकता है। आवेदक दो ग्रेडों अर्थात् टिटैनियम और लिथियम का उत्पादन नहीं करता।

3. तदनुसार विचाराधीन उत्पाद पोलिबूटाडिन रबड नियोडिमियम, कोबाल्ट और निकैल ग्रेडों के रूप नियोडिमियम के एचएस कोड 40 02 20 00 के तहत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद में पीवीआर के टिटैनियम और लिथियम ग्रेड शामिल नहीं है।

घरेलू उद्योग (डी आई)

4. आवेदन मैसर्स रिलाइंस इंडस्ट्रीज लिमि. द्वारा किया गया है। आवेदक कुल भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत उत्पादन करता है क्योंकि यह भारत में पीयूसी का एकमात्र उत्पादक है। इस प्रकार आवेदक नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग का हिस्सा है।

जांच की अवधि

5. वर्तमान जांच के उद्देश्यों से विचार की गई जांच की अवधि अप्रैल, 2015 से जून, 2019 तक है।

संबद्ध देश

6. वर्तमान जाँच में शामिल देश कोरिया आरपी है।

बढ़ा हुआ आयात

7. आवेदक ने यह दावा किया है कि आरपी कोरिया से विचाराधीन उत्पाद के आयात भारत में उत्पादन और खपत के साथ-साथ निरपेक्ष दृष्टि से बढ़े हैं। यह नोट किया जाता है कि हाल की अवधि में पीयूसी के आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अवधि, मात्रा, कुल आयात और भारत में खपत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि की दर काफी है।

घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों के कारण आवेदक को गंभीर क्षति हुई है। आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके लाभ, नकद लाभ, पीवीआईटी और आरओआई में गिरावट आई है।
9. आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में काफी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तत्काल द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच करने का अनुरोध किया है।
10. प्राधिकारी यह पाते हैं कि प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयात काफी बढ़ गए हैं जिससे भारत में इसी प्रकार की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और संबद्ध देश से बढ़े हुए आयातों के बीच कारणात्मक संबंध है और घरेलू उद्योग के लिए गंभीर क्षति का कारण है।

जांच की शुरुआत

11. यह निर्धारित करने के बाद की रक्षोपाय जांच की शुरुआत करने के लिए औचित्य ठहराने हेतु पर्याप्त साक्ष्य है, महा निदेशक यह निर्धारित करने के लिए कि आरपी कोरिया से विचाराधीन उत्पाद का आयात हुआ है, जो बढ़ा हुआ आयात है और यह कि आयात के कारण है अथवा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है, उपयुक्त मानते हैं।
12. सभी हितवद्ध पक्षकार अपने दृष्टिकोण से इस सूचना की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर निम्नलिखित को अवगत करा सकते हैं :

महा निदेशक
व्यापार उपचार महा निदेशालय
जीवन तारा बिल्डिंग, चतुर्थ तल,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

13. सभी जात हितवद्ध पक्षकारों को भी पृथक् रूप से पत्र भेजा जा रहा है।
14. इस जांच का कोई अन्य पक्षकार जो एक हितवद्ध पक्षकार के रूप में विचार किए जाने का इच्छुक है, अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है जोकि कि वह इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर महा निदेशक को पहुंच जाए।
15. यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना पूर्ण नहीं हो तब महा निदेशक अपने जांच परिणामों को रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकार्ड कर सकते हैं। इस सूचना को हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
16. गोपनीय आधार पर सूचना का प्रस्तुतिकरण : महा निदेशक के समक्ष प्रश्नावली का उत्तर सहित कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उसके साथ संलग्न अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों से यह अपेक्षा है कि वे उस स्थिति में दो अलग अलग सेटों में उसे प्रस्तुत करें जब “गोपनीयता” का दावा उसके किसी भाग के संबंध में किया जाए। “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” अनुरोधों को स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। इस प्रकार चिह्नित किये बिना किये गये किसी अनुरोध को महा निदेशक द्वारा अगोपनीय के रूप में माना जायेगा और महा निदेशक के पास यह स्वतंत्रता होगी कि वे अन्य हितवद्ध पक्षकारों को इस प्रकार के अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति दें। दोनों पाठों की सॉफ्ट प्रतियां हार्ड कॉपियों के साथ प्रत्येक के दो (2) सेटों में प्रस्तुत किया जाना भी अपेक्षित होगा। गोपनीय पाठ में वे सभी सूचनाएं शामिल रहेंगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं और/ अथवा अन्य सूचना जिसके बारे में इस प्रकार की सूचना देने वाले व्यक्ति गोपनीय के रूप में दावा करते हैं। यह सूचना जिसे गोपनीय प्रकृति के रूप में दावा किया जाता है अथवा वह सूचना जिस पर गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, यह सूचना देने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वे इसके संबंध में दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण उपलब्ध करायें कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है। अगोपनीय पाठ उस सूचना जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है पर निर्भर करते हुए अधिमान्य रूप से सूचीबद्ध अथवा खाली (यदि सूचीबद्ध करना संभव न हो) और संक्षिप्त रूप में गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए जिससे कि गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के तथ्यों को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालांकि, आपवादिक मामलों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि इस प्रकार की सूचना का संक्षेपण नहीं किया जा सकता है और उसके साथ ही उन कारणों का विवरण कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है, महा निदेशक की संतुष्टि के अनुसार अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए। महा निदेशक प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि महा निदेशक इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाला व्यक्ति सूचना को सार्वजनिक करने के लिए अथवा सामान्य या संक्षिप्त रूप में इसे प्रकट करने का अधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है तब वे इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं। सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना किया गया कोई अनुरोध अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सही कारण का विवरण दिये बिना किया गया कोई अनुरोध महा निदेशक द्वारा रिकार्ड पर नहीं लिया जाएगा। संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता के लिए आवश्यकतानुसार को स्वीकार करने पर महा निदेशक इस प्रकार की सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को इसे प्रकट नहीं करेंगे।
17. कोई हितवद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ निहित हो।
18. उस स्थिति में जहां कोई हितवद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना किसी अन्य को दिये जाने से इनकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है तब महा निदेशक अपने जांच परिणामों को अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकार्ड कर सकते हैं और केंद्र सरकार को इस प्रकार की सिफारिशें कर सकते हैं जिसे उपयुक्त माना गया हो।

सुनील कुमार, विशेष सचिव एवं महा निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION****(Bilateral Safeguard Investigation)**

New Delhi, the 7th November, 2019

Case No. (SG) 07/2019

Subject: Notice of initiation of Bilateral Safeguard Investigation concerning imports of “Polybutadiene Rubber” into India from Korea RP under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017

F. No. 22/7/2019-DGTR.—Whereas, an application has been filed under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter also referred to as the “said Rules”) by M/s. Reliance Industries Limited (hereinafter also referred to as the “Petitioner”) alleging increased imports of “Polybutadiene Rubber” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC” or subject goods) from Korea RP (also referred to as subject country) causing serious injury to the domestic producer of like or directly competitive product in India.

Product under Consideration (PUC)

2. The product under consideration is “Polybutadiene Rubber” classified under HS Code 40 02 20 00. Polybutadiene Rubber (also referred to as PBR) is a synthetic rubber that is a polymer formed from the polymerization of the monomer 1,3-butadiene. It is used in the manufacture of tyres mainly and is also used as an additive to improve the mechanical strength of plastics such as polystyrene and acrylonitrile butadiene styrene. The product is produced in more than one grade. The Petitioner has identified five grades, differentiated on the basis of the catalyst used in production. As per the Petitioner, the grades may be identified as: Neodymium, Cobalt, Nickel, Titanium and Lithium. The Petitioner does not produce two grades, i.e., Titanium and Lithium.
3. Accordingly, the product under consideration is “Polybutadiene Rubber” classified under HS Code 40 02 20 00 of Neodymium, Cobalt and Nickel grades. The product under consideration does not include titanium and lithium grades of PBR.

Domestic Industry

4. The application has been filed by M/s Reliance Industries Limited. The Petitioner accounts for 100% of total Indian production, as it is the sole producer of the PUC in India. Thus, Petitioner constitutes Domestic Industry as per the Rules.

Period of Investigation

5. The period considered for the purposes of present investigation is from April, 2015 to June, 2019.

Subject country

6. The country involved in the present investigation is Korea RP.

Increased Imports

7. The Petitioner has claimed that imports of product under consideration from Korea RP have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. It is noted that there is significant increase in imports of PUC in recent period. The rate of increase in imports of subject goods is considered significant considering the duration, the quantum, the total imports and the consumption in India.

Serious Injury to the domestic industry

8. The Petitioner has claimed that the increased imports of product under consideration has caused serious injury to it. The Petitioner has claimed that market share of domestic industry has declined whereas market share of subject imports has increased. They have also claimed that their profits, cash profits, PBIT and ROI have declined.
9. The Petitioner has requested for immediate imposition of bilateral safeguard measure in view of significant increase in imports of subject goods from subject country.
10. The Authority finds that there is prima facie evidence that imports of product under consideration have increased significantly causing serious injury to the domestic producers of the like article in India and there is

causal link between increased imports from subject country and the serious injury caused to the domestic industry.

Initiation

11. After determining that there is prima facie evidence to justify initiation of the safeguard investigation, the Director General considers appropriate to initiate the investigation in order to determine whether the imports of the product under consideration from Korea RP constitute increased imports and whether the increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic industry.
12. All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice to:

Director General
Directorate General of Trade Remedies
Jeevan Tara Building, 4th Floor
5, Parliament Street, New Delhi -110001

13. All known interested parties are also being addressed separately.
14. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General on aforementioned address within 30 days from the date of this notice.
15. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Director General may record its findings on the basis of the facts available on record. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.
16. Submission of Information on Confidential Basis—The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Director General and the Director General shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Director General. The Director General may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Director General is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Director General. The Director General, on being satisfied and accepting the need for keeping the information provided as confidential shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.
17. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.
18. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Director General may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Special Secy. & Director General